Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 11 Oct , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 08 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	21वां आसियान - भारत शिखर सम्मेलन
Page 09 **Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	एआई-जनरेटेड मेडिकल इमेज एक नई सीमा या संभावित नुकसान
Page 10 **Syllabus : GS 2 : शासन और सामाजिक न्याय**	क्या भारत मध्यम आय के जाल से बच सकता है?
समाचार में पुरस्कार	रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार
समाचार में टर्म	चावल का सुदृढ़ीकरण
Page 04 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति : न्यायपालिका**	भारत में मुकदमेबाजी का कठिन दौर

Page 08 : GS 2 : International Relations

21st ASEAN - India Summit

10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक को चिह्नित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार इसमें भाग लिया, आसियान नेताओं के साथ मिलकर आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आकलन किया और भविष्य के सहयोग को आकार दिया।

21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन: आसियान एकता और आर्थिक विकास पर ध्यान
- प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान एकता, आसियान केंद्रीयता और हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के लिए भारत के अटूट समर्थन को दोहराया।
- 21वीं सदी को "एशियाई सदी" कहते हुए उन्होंने एशिया के भविष्य को आकार देने में भारत-आसियान संबंधों के महत्व पर जोर दिया।

पिछले दशक की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- भारत-आसियान व्यापार को दोगुना करके 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करना
- सात आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान कनेक्टिविटी
- वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग और साझा सांस्कृतिक विरासत की बहाली
- नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान युवाओं के लिए छात्रवृत्ति

संवर्धित कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए 10-सूत्रीय योजना

- **"संयोजकता और लचीलेपन को बढ़ाना" के अध्यक्ष के विषय के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी ने 10-सूत्रीय योजना का अनावरण किया, जिसमें शामिल हैं:**
  1. संयुक्त गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना
  2. युवा शिखर सम्मेलन और स्टार्ट-अप फेस्टिवल जैसी जन-केंद्रित गतिविधियों के साथ एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक को चिह्नित करना
  3. आसियान-भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन
  4. नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति को दोगुना करना और भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में नई छात्रवृत्तियाँ जोड़ना
  5. 2025 तक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा करना
  6. आपदा लचीलापन बढ़ाने के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करना
  7. स्वास्थ्य लचीलापन बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों का ट्रैक शुरू करना
  8. आसियान-भारत साइबर नीति वार्ता की स्थापना करना
  9. ग्रीन हाइड्रोजन पर कार्यशाला आयोजित करना
  10. जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए 'माँ के लिए एक पेड़ लगाओ' अभियान शुरू करना

भावी कार्य योजना (2026-2030)

- नेताओं ने साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- आसियान-भारत साझेदारी को मजबूत करना: 2 संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया गया
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य
- डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की भूमिका को मान्यता देना

डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य:

मुख्य विशेषताएं

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का महत्व**
- आसियान डिजिटल मास्टरप्लान 2025 और सॉफ्टवेयर विकास में उत्कृष्टता केंद्रों में भारत के योगदान की सराहना की गई।

वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) सहयोग

- यह साझेदारी फिनटेक नवाचारों पर सहयोग का विस्तार करना चाहती है, विशेष रूप से सीमा पार भुगतान प्रणालियों और डिजिटल वित्तीय समाधानों के माध्यम से।

साइबर सुरक्षा सहयोग

- दोनों पक्षों ने डिजिटल अवसंरचना की लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आसियान-भारत साइबर नीति वार्ता की स्थापना का समर्थन किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहयोग

- संयुक्त वक्तव्य में कौशल, अवसंरचना, जोखिम प्रबंधन ढांचे और जिम्मेदार नीतियों को विकसित करने के लिए एआई में सहयोग का आह्वान किया गया।
- फोकस क्षेत्रों में कार्यबल को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करना और भरोसेमंद एआई सिस्टम को बढ़ावा देना शामिल है।

क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण

- डिजिटल परिवर्तन प्रयासों का समर्थन करने के लिए आसियान-भारत डिजिटल मंत्रियों की बैठक के तहत नियमित आदान-प्रदान, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और ज्ञान-साझाकरण पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्थायी वित्तपोषण और निवेश

- भारत और आसियान डिजिटल पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण सहित अभिनव वित्तपोषण तंत्रों का पता लगाने पर सहमत हुए।
- डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत कोष शुरू में इन गतिविधियों को वित्तपोषित करेगा।

आसियान

- **के बारे में**
- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य अपने दस सदस्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है:
- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- तिमोर-लेस्ते 2022 में एक पर्यवेक्षक के रूप में आसियान में शामिल हो गया। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।
- आसियान देशों की कुल जनसंख्या 662 मिलियन है और 2022 तक इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.6 ट्रिलियन डॉलर है।
- आसियान का एक गान, एक ध्वज और द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन (वर्ष में दो बार) होता है, जिसमें एक घूर्णन अध्यक्षता होती है।

स्थापना:

- इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणापत्र) पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी, जिस पर आसियान के संस्थापक पिता इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे।
- उद्देश्य: आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" है।
- सचिवालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।

आसियान के साथ भारत के संबंध

- **आसियान और एक्ट ईस्ट नीति**
  - आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है।
- **संवाद भागीदारों में भारत**
  - भारत आसियान प्लस सिक्स समूह का हिस्सा है, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

व्यापार और निवेश

- 2010 में, माल में भारत-आसियान एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेवाओं में एफटीए पर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत और आसियान महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं, आसियान भारत के वैश्विक व्यापार का 11% हिस्सा है।
- भारत और आसियान ने 2022-23 में 131.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया।
- 2023-24 में, दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन डॉलर था।

- भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा है, 2023-24 में आसियान देशों को 41.21 बिलियन डॉलर का निर्यात किया जाएगा, जबकि 79.67 बिलियन डॉलर का आयात किया जाएगा।

संस्थागत सहयोग

- **2002 में भारत-आसियान शिखर-स्तरीय साझेदारी;**
  · वर्ष 2022 में आसियान-भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
- 2012 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।
- भारत और आसियान ने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM+) के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत किया है।
- पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME) 2023 में आयोजित किया गया था।

पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना

- सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया।
- आसियान-भारत पर्यटन सहयोग कार्य योजना 2023-2027 का कार्यान्वयन।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

जैसा कि हम विचार करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला रही है, एक उभरता हुआ क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा में सिंथेटिक चिकित्सा छवियों का उपयोग है।

AI-generated medical images: a new frontier or potential pitfall?

The demand for high-quality, annotated medical images far exceeds supply. Real-world images, such as those generated by the MRI and CT scans, are expensive and time-consuming to collect. Synthetic medical images can bridge this gap by providing an ethical, scalable, and cost-effective solution

C. Aravinda

In a world where even the experts are sometimes puzzled by our economic systems, only a tiny fraction of economists truly understand the mechanics that govern them. Imagine what would happen if these experts were replaced by artificial intelligence (AI). Would we still trust our monetary systems? This thought experiment becomes particularly relevant while considering the rapid rise of synthetic medical images in healthcare.

AI generates entirely new medical scans or radiological images that mimic real ones but are not derived from any actual patient data. GETTY IMAGES

What are synthetic medical images?

At its core, a synthetic medical image is generated by AI or computer algorithms without being captured by traditional imaging devices such as MRI, CT scans, or X-rays. These images are entirely constructed using mathematical models or AI techniques like generative adversarial networks (GANs), diffusion models, and autoencoders.

Synthetic images are like the concept of "this person does not exist" images, where the AI creates images of people who do not actually exist in the real world. In the medical field, synthetic medical images are created in a similar way, where the AI generates entirely new medical scans or radiological images that mimic real ones but are not derived from any actual patient data.

In healthcare, the demand for high-quality, annotated medical images far exceeds supply. Real-world medical images, such as those from MRI, CT scans, or X-rays, are expensive and time-consuming to collect. Additionally, privacy concerns around patient data limit the sharing of these images across medical institutions and research labs. Synthetic medical images can bridge this gap by providing an ethical, scalable, and cost-effective solution.

How are these images created? A variational autoencoder (VAE) takes an image, compresses it into a simpler form called the latent space, and then tries to recreate the original image from that compressed version. The process continuously improves the image by minimising the difference between the real image and the recreated version.

GANs involve a generator that creates synthetic images from random data and a discriminator that determines whether the image is real or synthetic. Both improve through competition—the generator tries to make its images more realistic, while the discriminator gets better at spotting fakes.

Diffusion models begin with a bunch of random noise and gradually transform it into a realistic image, using a step-by-step process that slowly shapes the noise into something that resembles the images it was trained on. These methods generate synthetic images in various fields.

Advantages of synthetic images

One significant advantage of synthetic medical images is their ability to facilitate intra- and inter-modality translation. Intramodality translation refers to generating synthetic images within the same type of imaging modality, such as improving or reconstructing MRI scans based on other MRI data. Inter-modality translation, on the other hand, involves generating synthetic images by translating between different types of imaging modalities, such as creating CT scans from MRI data. This ability to move across and within modalities is invaluable in cases where certain scans are unavailable or incomplete. Synthetic images can fill these gaps by creating accurate representations from other types of data.

Privacy is another significant advantage. Since synthetic images are generated without patient data, they circumvent privacy concerns, making it easier for researchers and healthcare providers to share and collaborate on AI development without the risk of violating patient confidentiality.

Synthetic medical images also address the time and cost of collecting real medical data.

Challenges ahead

Synthetic data algorithms have the potential for malicious applications, including introducing deepfakes into hospital systems.

Deepfakes may impersonate individual patients, introducing clinical findings that do not exist, which could lead to incorrect diagnoses or treatments. Worse yet, they could be exploited to submit fraudulent claims to health insurers, creating a pathway for financial exploitation.

These images are entirely constructed using mathematical models or AI techniques like generative adversarial networks, diffusion models, and autoencoders

Synthetic images might lack the complexity and nuances of real-world medical data. For instance, while a synthetic brain MRI might look accurate, it may not capture the subtle variations in tissue density or lesion patterns found in real-world cases.

The AI model's performance may worsen over time due to the absence of rich, real-world variability.

What if, over time, our AI systems, trained on synthetic medical data, begin to rely more on fabricated images than on real-world cases? This is where the issue of truth erosion comes into play.

As synthetic medical images become more prevalent, the distinction between what is real and what is generated may blur, making it harder for medical professionals to trust AI diagnoses based solely on synthetic data.

Suppose AI systems are trained exclusively on synthetic medical images, generating diagnoses that don't align with real-world cases.

Over time, this could lead to an entire diagnostic model based on artificial realities rather than true patient data.

Collaborative solution and caution

One effective way to mitigate these risks and improve the quality of synthetic medical images is through close collaboration between clinicians (such as radiologists) and AI engineers.

When developing AI models, clinicians can provide critical insights from real-world medical practice, helping AI engineers understand the complexities and nuances often missing from synthetic data. Their collaboration can lead to AI models that score better in evaluation metrics, resulting in real-life clinical utility.

While synthetic medical images hold the potential for improving healthcare, their widespread use comes with risks. Just as we wouldn't leave the decision of printing physical currency entirely to an AI system, we should be cautious about relying too heavily on synthetic medical images to shape our understanding of human health.

Reality is stranger than fiction. Synthetic images won't be able to generate those strange realities.

They pose significant regulatory and ethical challenges. Human oversight remains critical to ensuring that AI-generated content serves the best interests of patients and healthcare providers.

The balance between innovation and truth is delicate, and only time will tell whether synthetic images will enhance or distort our understanding of health.

We must proceed with optimism and caution, ensuring that the benefits of synthetic images are realised without compromising the integrity of real-world healthcare.

(Dr. C. Aravinda is an academic and a public health physician. aravindaaiimsjr10@hotmail.com)

सिंथेटिक मेडिकल इमेज क्या हैं?

- सिंथेटिक मेडिकल इमेज AI द्वारा जनरेटेड इमेज हैं, जो MRI, CT स्कैन या एक्स-रे जैसे पारंपरिक इमेजिंग डिवाइस का उपयोग किए बिना बनाई जाती हैं।
- ये इमेज गणितीय मॉडल या AI तकनीकों, जैसे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN), डिफ्यूजन मॉडल और ऑटोएनकोडर का उपयोग करके बनाई जाती हैं।

दिए जाने वाले लाभ

- इंट्रा- और इंटर-मोडैलिटी ट्रांसलेशन: एक ही या अलग-अलग तरह के स्कैन से इमेज जनरेट करें, जब कुछ स्कैन उपलब्ध न हों तो मदद करें।
- गोपनीयता सुरक्षा: रोगी डेटा के बिना बनाया गया, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को कम करता है और शोध के लिए डेटा साझा करना आसान बनाता है।
- लागत और समय दक्षता: वास्तविक मेडिकल स्कैन की तुलना में सिंथेटिक इमेज बनाना तेज़ और सस्ता है।
- स्केलेबिलिटी: AI प्रशिक्षण और शोध के लिए बड़ी मात्रा में मेडिकल डेटा का उत्पादन करना आसान है।

चुनौतियाँ

- दुरुपयोग की संभावना: इसका उपयोग मेडिकल डीपफेक बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी वाले दावे या नकली नैदानिक निष्कर्ष सामने आ सकते हैं।
- वास्तविक दुनिया की जटिलता का अभाव: वास्तविक चिकित्सा डेटा में पाए जाने वाले सूक्ष्म विवरणों को कैप्चर नहीं कर सकता है, जिससे संभावित रूप से निदान सटीकता कम हो सकती है।
- सत्य का क्षरण: सिंथेटिक डेटा पर बहुत अधिक निर्भर रहने से AI मॉडल विकृत हो सकते हैं, जिससे ऐसे निदान हो सकते हैं जो वास्तविक दुनिया के मामलों से मेल नहीं खाते।
- नैतिक और विनियामक चिंताएँ: दुरुपयोग से बचने के लिए इन छवियों को कैसे नियंत्रित और मॉनिटर किया जाना चाहिए, इस बारे में प्रश्न।

Page 10 : GS 2 : Governance and Social Justice : Poverty & Hunger

विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में "मध्यम आय जाल" पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ विकास धीमा होने पर अर्थव्यवस्थाएँ स्थिर हो जाती हैं। 34 वर्षों में केवल 34 मध्यम आय वाले देश ही उच्च आय की स्थिति में पहुँच पाए हैं।

Can India escape middle-income trap?

How does the World Bank define the threshold for middle-income economies? Why is state intervention considered crucial for breaking the middle-income trap? What lessons can be drawn from South Korea and Chile? What challenges does India face in balancing state intervention with democratic values?

ECONOMIC NOTES

Rahul Menon

The World Development Report 2024 – authored by the World Bank – calls attention to the phenomenon of the "middle-income" trap, or the slowing down of growth rates as incomes increase. The World Bank estimates a stagnation of income per capita when economies reach a level of per capita incomes 11% of that of the U.S., hindering their journey to high-income status. Over the last 34 years, only 34 middle-income economies – defined as economies with per capita incomes between $1,136 and $13,845 – have transitioned to higher income levels.

The WDR details the policies and strategies necessary to break out of the trap based on the development experiences of those countries that did manage the transition. It highlights the importance of the "3i" approach: investment, infusion, and innovation. Economies must invest, ensure the infusion of new global technologies, and develop an environment conducive to domestic innovation. This is no easy task and requires nimble and responsive state policy. In the modern economy, there are plenty of headwinds that India must overcome to successfully navigate the middle-income trap.

Role of the state

Most countries that broke the trap were part of the European Union which facilitated growth and mobility of capital and labour for its members. Such institutions that aid free factor mobility are not available for most countries, for whom capital inflows are liberalised – largely flowing into their economies – with restrictions on the movement of labour. An important non-European country that managed to escape the trap is South Korea.

GETTY IMAGES

The South Korean state was heavily interventionist, often directing the private sector's activities and ensuring their participation in an export-driven growth model. Successful companies were rewarded with access to new technologies and other supportive measures, while firms that did not perform were allowed to fail. This was no pure free market, but one where a powerful state intervened to bring about developmental goals, disciplining local elites and ensuring they followed the dictates of the state's economic plan.

Another economy that broke the middle-income trap was Chile. But it too, saw state intervention in ensuring the success of natural resource exporting sectors. The salmon industry, for instance, succeeded in Chile due to the targeted intervention of the state on multiple fronts to ensure that the industry flourished.

The South Korean government's approach carries significant lessons for India today. The state must be seen as being neutral amongst private players and ensuring those who do not make the mark are allowed to fail. The benefits firms receive from the state must be based on their performance instead of closeness to power. The presence of powerful business houses can promote growth provided they invest, ensure the adoption and infusion of new technologies, and innovate. South Korean business houses, or chaebols, are among the leaders in innovation today.

The pitfalls

South Korea's success was built on manufacturing exports; such a strategy is not possible in today's economic scenario. World export growth has slowed, with demand from large economies slowing down following the multiple shocks of the last few years. Several countries have seen a slow turn to protectionism. The employment losses in developed economies caused by free trade have made it more difficult for countries such as India to access foreign markets.

Moreover, several countries have been hit by what economist Dani Rodrik terms 'premature deindustrialisation'. Modern economies face a reduction in the income share of manufacturing at much lower levels of GDP compared to previous economies. Manufacturing is no longer an engine of growth for developing economies, and it remains to be seen whether the service sector is strong enough to break the trap.

Challenges facing India

The power of billionaires in the Indian economy has increased, and they are seen as being close to the state, with the state unable – or unwilling – to ensure high rates of investment from domestic capital. The manufacturing sector has stagnated, and there has been a reversal of the process of structural transformation, with employment increasing in agriculture and in low-productive forms following the pandemic.

The growth of the aggregate economy is not being reflected on the ground. While the government estimates a real GDP growth of around 7% in recent years, wages have not kept up. According to the PLFS, nominal wages for regular wage workers at the all-India level between April and June 2023-24 has only grown at around 5%, and that of casual workers at roughly 7%. With an inflation rate of roughly 5% during this time, this implies that wage earners have seen little to no real wage growth. An economy cannot break a middle-income trap if workers are unable to partake in the growth process, as reduced consumption demand will become a drag on the economy.

Most importantly, the question of democracy looms large. South Korea's export strategy was overseen by a military government that ruled till the 1980s. The government frequently quelled labour unions to aid the accumulation process of capital. Chile deposed the democratically elected government of Salvador Allende by a military coup, installing General Augusto Pinochet as the head of state. It is vital not to take the wrong lessons from these countries, and think that democracy is an acceptable price to pay for higher growth. The challenge for policy is to promote state intervention to ensure growth while maintaining the sanctity of the democratic ethos.

Rahul Menon is Associate Professor in the Jindal School of Government and Public Policy at O.P. Jindal Global University

THE GIST

- The middle-income trap refers to the slowdown of growth as economies reach middle-income status, with only 34 countries successfully transitioning to high-income levels in the last 34 years.
- Breaking the middle-income trap requires policies focused on investment, infusion of global technologies, and fostering domestic innovation, supported by flexible and responsive state policies.
- India's challenge is to foster growth through strategic state intervention while preserving democratic principles and ensuring inclusive participation in the growth process.

विश्व बैंक मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा को कैसे परिभाषित करता है?

- विश्व बैंक मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं को उन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जिनकी आय प्रति व्यक्ति $1,136 और $13,845 के बीच है।
- मध्यम आय जाल का तात्पर्य विकास में मंदी से है जब कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित आय सीमा तक पहुँच जाती है, जो कि यू.एस. की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 11% है।
- पिछले 34 वर्षों में केवल 34 मध्यम आय वाले देश उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुए हैं, जो मध्यम आय के जाल से बाहर निकलने की कठिनाई को दर्शाता है।

मध्यम आय के जाल को तोड़ने के लिए राज्य का हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है?

- विकास लक्ष्यों के समन्वय के लिए राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, जैसा कि दक्षिण कोरिया और चिली में देखा गया है, जहाँ सरकारों ने उद्योगों को आकार देने और राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों के साथ निजी क्षेत्र के संरेखण को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
- राज्य निवेश, वैश्विक प्रौद्योगिकियों का संचार और घरेलू नवाचार सुनिश्चित करता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे 3i दृष्टिकोण (निवेश, संचार, नवाचार) के रूप में जाना जाता है।
- राज्य का हस्तक्षेप स्थानीय अभिजात वर्ग को अनुशासित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फर्म राजनीतिक संबंधों के बजाय प्रदर्शन के आधार पर सफल हों। खराब प्रदर्शन करने वाली फर्मों को विफल होने दिया जाता है, जिससे दक्षता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

दक्षिण कोरिया और चिली से क्या सबक लिया जा सकता है?

- दक्षिण कोरिया ने निर्यात-संचालित विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के नेतृत्व वाली औद्योगिकीकरण रणनीति अपनाई:
  - o राज्य ने निजी क्षेत्र की गतिविधियों को सक्रिय रूप से निर्देशित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यवसाय वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी हों।
  - o चैबोल्स (बड़े व्यापारिक समूह) को उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन दिया गया, जिससे तकनीकी उन्नति और नवाचार को बढ़ावा मिला।

चिली ने अपने सामन उद्योग जैसे प्राकृतिक संसाधन निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके सफलता हासिल की:

- o विकास क्षमता वाले उद्योगों को विकसित करने और उनका समर्थन करने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यह दर्शाता है कि कैसे लक्षित हस्तक्षेप छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पनपने में मदद कर सकते हैं।

भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ राज्य के हस्तक्षेप को संतुलित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- आर्थिक शक्ति संकेन्द्रण: भारत को शक्तिशाली व्यापारिक घरानों के बीच धन के बढ़ते संकेन्द्रण का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें राज्य से निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह प्रदर्शन-आधारित विकास के बजाय भाई-भतीजावाद का जोखिम उठाता है, जो नवाचार और निवेश में बाधा डाल सकता है।
- विनिर्माण में ठहराव: दक्षिण कोरिया के विपरीत, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। वैश्विक निर्यात मांग में कमी और संरक्षणवाद में वृद्धि के साथ, विनिर्माण भारत के विकास को गति देने में कम सक्षम है।
- वेतन में स्थिरता: वास्तविक वेतन वृद्धि स्थिर रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति नाममात्र वेतन वृद्धि के लाभों को नष्ट कर देती है। यह घरेलू मांग को सीमित करता है, जो आर्थिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण कारक है।
- समय से पहले विऔद्योगीकरण: भारत, कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरह, समय से पहले विऔद्योगीकरण का सामना कर रहा है, जिसका अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान ऐतिहासिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आय के निचले स्तर पर घट रहा है।
- लोकतंत्र के साथ राज्य के हस्तक्षेप को संतुलित करना: दक्षिण कोरिया और चिली ने सत्तावादी शासन के तहत आक्रामक राज्य हस्तक्षेप को लागू किया। हालाँकि, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की रणनीतियाँ लोकतांत्रिक मूल्यों और श्रम अधिकारों की कीमत पर न हों।

मध्यम आय के जाल से बचने के लिए विश्व बैंक की सिफारिश

- विश्व विकास रिपोर्ट 2024: यह रिपोर्ट मध्यम आय वाले देशों के लिए जाल से बचने के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है:
  - निवेश: शुरुआत में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।

- प्रौद्योगिकी संचार: घरेलू उद्योगों में आधुनिक तकनीकों को शामिल करना।
- नवाचार: अंततः प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना

आगे की राह:

- आर्थिक विकास रणनीति: नीति आयोग के सीईओ ने मध्यम आय के जाल से बचने के लिए एक व्यापक आर्थिक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे उन्होंने भारत के विकास के लिए "सबसे बड़ा खतरा" बताया।
- मुक्त व्यापार और वैश्विक एकीकरण: नीति आयोग के सीईओ ने मुक्त व्यापार के लिए खुलेपन को बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ संरेखण की वकालत की।
- शहरी विकास और बुनियादी ढाँचा: सरकार को शहरी क्षेत्रों को आर्थिक केंद्रों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसे विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

Award In News : Nobel Prize in Chemistry

2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम. जम्पर को प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाएगा।

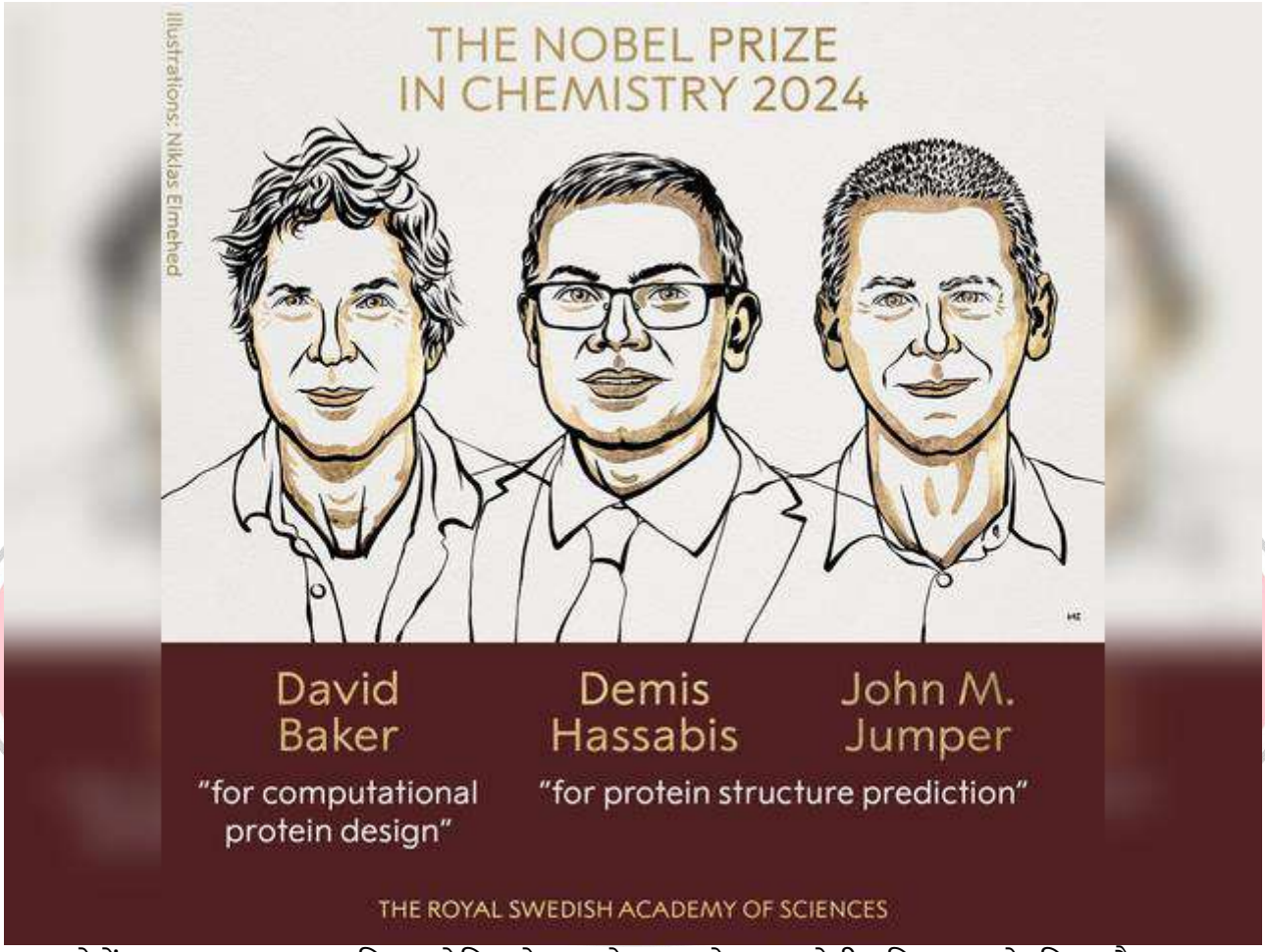

- प्रमुख खोजें: पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को 'कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन' के लिए और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसबिस और जॉन एम. जम्पर को 'प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी' के लिए दिया गया।
- महत्व: डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रोटीन डिज़ाइन करने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर ने 50 साल पुरानी चुनौती- प्रोटीन की जटिल 3-डी संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल विकसित किया।
    - बेकर के समूह ने 2003 से ही कई नए प्रोटीन बनाए हैं, जिनका फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, नैनोमटेरियल, सेंसर और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया गया है।
    - हसबिस और जम्पर ने 2020 में AI-आधारित मॉडल को अल्फाफोल्ड2 नाम दिया। यह आज तक पहचाने गए लगभग सभी 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी कर सकता है।
    - अल्फाफोल्ड2 का उपयोग दुनिया भर के लाखों वैज्ञानिकों द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोध और प्लास्टिक क्षरण जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है।

Term In News : Rice Fortification

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने वाली सभी केंद्र सरकार की योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को इसके वर्तमान स्वरूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है।

चावल फोर्टिफिकेशन के बारे में:

- फोर्टिफिकेशन, सामान्य चावल में 1:100 के अनुपात में (1 किलोग्राम FRK को 100 किलोग्राम कस्टम मिल्ड चावल के साथ मिलाकर) FSSAI-निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) को मिलाने की प्रक्रिया है।
- फोर्टिफाइड चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान है। यह प्रक्रिया चावल की मिलिंग के समय चावल मिलों में की जाती है।
- यह उच्च प्रति व्यक्ति चावल की खपत वाले देशों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक लागत प्रभावी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त रणनीति है।
- चावल फोर्टिफिकेशन एक 2-चरणीय प्रक्रिया है - (1) फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) का उत्पादन (2) FRK के साथ चावल का मिश्रण

चावल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन है

- नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए कोटिंग, डस्टिंग और 'एक्सट्रूज़न' जैसी विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं।

- सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ने की तकनीक में 'एक्सट्रूडर' मशीन का उपयोग करके मिश्रण से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) का उत्पादन शामिल है। इसे भारत में सबसे अच्छी तकनीक माना जाता है।
- सूखे चावल के आटे को सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रीमिक्स के साथ मिलाया जाता है और इस मिश्रण में पानी मिलाया जाता है, जिसे फिर हीटिंग ज़ोन वाले ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर से गुज़ारा जाता है।
- चावल के आकार और माप के समान कर्नेल का उत्पादन किया जाता है, जो "जितना संभव हो सके सामान्य मिल्ड चावल जैसा दिखना चाहिए"।
- कर्नेल को सुखाया जाता है, ठंडा किया जाता है और पैक किया जाता है। FRK की शेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने होती है।
- फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए कर्नेल को नियमित चावल के साथ मिलाया जाता है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत, 10 ग्राम FRK को 1 किलोग्राम नियमित चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए।
- एफएसएसएआई के मानदंडों के अनुसार, 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे: आयरन (28 मिलीग्राम-42.5 मिलीग्राम), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम), और विटामिन बी-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम)।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 04 Editorial Analysis

The gruelling course of litigation in India

Gokul Krishnan R.

Project Associate at DAKSH, an organisation working on judicial reforms

Ninni Susan Thomas

a lawyer based in New Delhi and a consultant with DAKSH

Last month, the President of India, Droupadi Murmu, highlighted the issue of court delays. In her speech at the National Conference of the District Judiciary, she noted that these delays are what are making people hesitate approaching courts, as they fear that the pursuit of justice will complicate their lives further. She referred to this as the 'black coat syndrome', likening it to white coat hypertension – a condition where patients exhibit elevated blood pressure in clinical settings. While the term is symbolic, it underscores a real issue – that many people are reluctant to engage in litigation due to the gruelling process, which includes endless adjournments, numerous appeals, and escalating legal costs. A significant factor contributing to these delays is the Indian judiciary's scheduling and case management practices. Effective case management, involving clear timelines for filing documents, conducting witness examinations, scheduling hearings, and limiting adjournments, are crucial. Without these, the court system struggles to move cases forward efficiently, exacerbating delays and frustrations faced by litigants.

Court scheduling and case management have long been challenges within the Indian judiciary, significantly contributing to delays. Mechanisms such as Case Flow Management Rules were introduced for district and High Courts to streamline processes, set timelines, and create more predictable court schedules. However, despite their introduction in the late 2000s, these rules and other initiatives, that were aimed at improving scheduling and timely case disposal, have been inconsistently implemented, and with limited impact.

At the level of the district judiciary

While stricter rules and rigid timelines are often suggested as solutions, the reality is more complex. It is crucial to recognise that all participants in the judicial system – judges, lawyers, litigants and witnesses – act with rationality and good intentions, though their actions are often influenced by various constraints and incentives. Court scheduling issues are deeply rooted in the complex interplay of these motivations. A holistic approach that considers the psychological and behavioural aspects of all stakeholders is essential for meaningful progress. Let us look at the challenges in the district judiciary.

Judges have a crucial role in enforcing case management timelines. But systemic pressures often compromise their ability to do so. Judges in the district judiciary have to prioritise cases, with directions from higher courts to dispose of these cases within a specific time or where target disposal numbers have been provided for case types. While such oversight aims to ensure timely justice, higher courts often impose deadlines without fully considering their impact on the overall scheduling in district courts. This forces district courts to allocate disproportionate resources to expedite certain cases, disrupting scheduling and creating delays. The Supreme Court of India and various High Courts have criticised this trend, noting that such directives often disrupt case management in district courts. A more balanced approach is needed, wherein higher courts' deadlines align with district court operational realities to avoid exacerbating delays.

Various statutes and rules impose timelines for the disposing of cases or filing documents, but judges are often not incentivised to adhere to these deadlines. When extensions are permissible, judges frequently grant them beyond statutory deadlines, knowing that higher courts are likely to condone such delays if appealed. Judges who enforce these deadlines may face pressure from the bar, potentially affecting their career progression as they risk being labelled 'difficult' and subjected to constant complaints.

The performance evaluation system for judges of the district judiciary, known as the units system, exacerbates these challenges. Judges are awarded "units" or points based on the type and number of cases they dispose of, with different weights assigned to different case types. To maximise their units, judges might prioritise and dispose of the simpler cases quickly, allowing them to accumulate points more quickly. This can lead to a situation where judges focus on less complex cases to boost their unit count, potentially neglecting the more challenging cases that require substantial judicial intervention. By favouring cases that are easier to resolve and quicker to process, judges may inadvertently contribute to delays in more complex cases, which are sidelined or postponed.

Court scheduling and case management continue to be a hurdle that litigants face

The impact down the line

Lawyers significantly impact court scheduling and case management. Often handling multiple cases scheduled across different courts on the same day, they strategically decide about which cases to attend to based on factors such as the likelihood of adjournment, the importance of the case, or the perceived mood and predispositions of a particular judge. This often leads to adjournments in some matters.

The lack of predictability in case hearings exacerbates this issue. Lawyers often do not have a clear understanding of when a particular case will be heard or the likelihood of adjournment, making it difficult to plan their schedules. Moreover, lawyers may request adjournments or deliberately delay proceedings if they perceive that the judge is likely to grant an adjournment, especially if their client has expressly asked for it. This lack of predictability and the strategic behaviour it encourages only adds to the congestion in court schedules.

The tendency to extend stays and interim orders further diminishes the interest of lawyers in actively pursuing a case. For litigants, obtaining a stay on a case can often be seen as a victory, especially in civil matters where a stay order may prevent any immediate adverse action. Consequently, once a stay is obtained, there may be little incentive in pushing for a speedy resolution, contributing to the backlog of cases.

Before a trial begins, the judge sets a schedule with specific dates for each witness's testimony, and, accordingly, summons are issued. However, the timing of testimonies often becomes unpredictable due to changes in the court schedule, adjournments, and procedural delays. This disrupts daily life for witnesses, forcing them to leave their jobs, make travel arrangements and put personal responsibilities on hold, often without knowing when they would have to testify. The lack of a predictable schedule frustrates witnesses, is a financial strain, discourages their court appearances and contributes to trial delays.

Need for holistic reform

To address court scheduling issues, a holistic approach is needed that goes beyond rules and timelines, and which focuses on incentivising all actors. Judges should be evaluated not just by the number of cases they dispose of but also by their ability to manage and resolve more complex cases within the prescribed timelines. The unit system needs reform so as to prioritise complex cases that require substantial judicial intervention, encouraging a broader range of case management. Lawyers need better scheduling information to reduce uncertainty and avoid unnecessary adjournments. Courts should implement predictable scheduling systems, introduce penalties for delays, and reward lawyers who adhere to schedules. Litigants should be discouraged from using stay orders and interim reliefs as delay tactics by making such orders temporary and subject to regular review. Witnesses require more predictability in court appearances, with advance notice and sufficient compensation beyond travel expenses to encourage their participation.

Technological solutions could enhance case management, providing real-time updates and the monitoring of timelines. Courts can adopt a data-driven approach to identify and address scheduling bottlenecks, improving overall judicial efficiency. Without reform that accounts for the human side of the system, any procedural changes will remain just that – paper reforms.

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति: न्यायपालिका

UPSC Mains Practice Question : भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रमुख सुधारों पर चर्चा करें। (250 w/15m)

संदर्भ :

- जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में, अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने अदालती देरी की समस्या पर जोर दिया।
- उन्होंने बताया कि इन देरी के कारण लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने में हिचकिचा रहे हैं।

परिचय

- पिछले महीने, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदालती देरी के मुद्दे पर प्रकाश डाला। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि इन देरी के कारण लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि न्याय की तलाश उनके जीवन को और जटिल बना देगी।
- उन्होंने इसे 'ब्लैक कोट सिंड्रोम' के रूप में संदर्भित किया, इसकी तुलना व्हाइट कोट हाइपरटेंशन से की - एक ऐसी स्थिति जिसमें रोगी नैदानिक सेटिंग्स में उच्च रक्तचाप प्रदर्शित करते हैं।
- हालांकि यह शब्द प्रतीकात्मक है, लेकिन यह एक वास्तविक मुद्दे को रेखांकित करता है - कि कई लोग थकाऊ प्रक्रिया के कारण मुकदमेबाजी में शामिल होने से हिचकते हैं, जिसमें अंतहीन स्थगन, कई अपील और बढ़ती कानूनी लागत शामिल हैं।

न्यायिक देरी में योगदान देने वाले कारक

- इन देरी में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय न्यायपालिका की समय-सारणी और केस प्रबंधन प्रथाएँ हैं।
- प्रभावी केस प्रबंधन: दस्तावेज़ दाखिल करने, गवाहों की परीक्षा आयोजित करने, सुनवाई का समय निर्धारित करने और स्थगन को सीमित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ शामिल करना महत्वपूर्ण है।
- इनके बिना, न्यायालय प्रणाली मामलों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करती है, जिससे वादियों द्वारा सामना की जाने वाली देरी और निराशा बढ़ जाती है।
- न्यायालय की समय-सारणी और केस प्रबंधन लंबे समय से भारतीय न्यायपालिका के भीतर चुनौतियाँ रही हैं, जो देरी में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती हैं।
- प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, समय-सीमा निर्धारित करने और अधिक पूर्वानुमानित न्यायालय कार्यक्रम बनाने के लिए जिला और उच्च न्यायालयों के लिए केस फ्लो प्रबंधन नियम जैसे तंत्र पेश किए गए थे।
- असंगत कार्यान्वयन: हालाँकि, 2000 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी शुरूआत के बावजूद, ये नियम और अन्य पहल, जिनका उद्देश्य समय-सारणी में सुधार और केस का समय पर निपटान करना था, असंगत रूप से लागू किए गए हैं, और इनका प्रभाव सीमित है।

जिला न्यायपालिका के स्तर पर

- कड़े नियमों को लागू करने की चुनौती: जबकि कड़े नियमों और कठोर समयसीमाओं को अक्सर समाधान के रूप में सुझाया जाता है, वास्तविकता अधिक जटिल है।
  o यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि न्यायिक प्रणाली में सभी प्रतिभागी - न्यायाधीश, वकील, वादी और गवाह - तर्कसंगतता और अच्छे इरादों के साथ कार्य करते हैं, हालांकि उनके कार्य अक्सर विभिन्न बाधाओं और प्रोत्साहनों से प्रभावित होते हैं।

न्यायालय के शेड्यूलिंग मुद्दे इन प्रेरणाओं के जटिल परस्पर क्रिया में गहराई से निहित हैं

- एक समग्र दृष्टिकोण: जो सभी हितधारकों के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करता है, सार्थक प्रगति के लिए आवश्यक है। आइए जिला न्यायपालिका में चुनौतियों पर नज़र डालें।

जिला न्यायपालिका में चुनौतियाँ

- न्यायाधीशों की भूमिका: केस प्रबंधन समयसीमा को लागू करने में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
  o लेकिन प्रणालीगत दबाव अक्सर ऐसा करने की उनकी क्षमता से समझौता करते हैं। जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों को मामलों को प्राथमिकता देनी होती है, उच्च न्यायालयों से इन मामलों को एक विशिष्ट समय के भीतर निपटाने के निर्देश या जहां केस प्रकारों के लिए लक्ष्य निपटान संख्या प्रदान की गई है।
- निरीक्षण का प्रभाव: जबकि इस तरह के निरीक्षण का उद्देश्य समय पर न्याय सुनिश्चित करना है, उच्च न्यायालय अक्सर जिला न्यायालयों में समग्र समय-निर्धारण पर उनके प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना समय-सीमाएँ लागू करते हैं।
  o यह जिला न्यायालयों को कुछ मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए असंगत संसाधनों को आवंटित करने के लिए मजबूर करता है, जिससे समय-निर्धारण बाधित होता है और देरी होती है।
  o भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस प्रवृत्ति की आलोचना की है, यह देखते हुए कि इस तरह के निर्देश अक्सर जिला न्यायालयों में केस प्रबंधन को बाधित करते हैं।
  o अधिक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें उच्च न्यायालयों की समय-सीमाएँ जिला न्यायालय की परिचालन वास्तविकताओं के साथ संरेखित हों ताकि देरी को बढ़ने से रोका जा सके।
- **न्यायाधीशों के लिए समय-सीमा लागू करने के लिए प्रोत्साहन की कमी:** विभिन्न क़ानून और नियम मामलों के निपटान या दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए समय-सीमाएँ लागू करते हैं, लेकिन न्यायाधीशों को अक्सर इन समय-सीमाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।
  o जब विस्तार की अनुमति होती है, तो न्यायाधीश अक्सर उन्हें वैधानिक समय-सीमाओं से परे देते हैं, यह जानते हुए कि उच्च न्यायालय अपील किए जाने पर ऐसी देरी को माफ कर सकते हैं।
  o जो न्यायाधीश इन समयसीमाओं को लागू करते हैं, उन्हें बार से दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो संभावित रूप से उनके करियर की प्रगति को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उन्हें 'कठिन' करार दिए जाने और लगातार शिकायतों के अधीन होने का जोखिम होता है।

जिला न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली यूनिट सिस्टम:

- जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, जिसे यूनिट सिस्टम के रूप में जाना जाता है, इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है।
  o न्यायाधीशों को उनके द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार और संख्या के आधार पर "यूनिट" या अंक दिए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों को अलग-अलग भार दिया जाता है।
  o अपनी यूनिट को अधिकतम करने के लिए, न्यायाधीश सरल मामलों को प्राथमिकता दे सकते हैं और जल्दी से निपटा सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक तेज़ी से अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- सरल मामलों पर ध्यान दें: इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहाँ न्यायाधीश अपनी इकाई संख्या बढ़ाने के लिए कम जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संभावित रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण मामलों की उपेक्षा करते हैं, जिनमें पर्याप्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
  o ऐसे मामलों को प्राथमिकता देकर, जिन्हें सुलझाना आसान है और जिन्हें जल्दी से निपटाया जा सकता है, न्यायाधीश अनजाने में अधिक जटिल मामलों में देरी में योगदान दे सकते हैं, जिन्हें दरकिनार कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है।

भविष्य में प्रभाव

- वकीलों द्वारा रणनीतिक निर्णय लेना: वकील अदालत के शेड्यूलिंग और केस प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
  o अक्सर एक ही दिन में विभिन्न अदालतों में निर्धारित कई मामलों को संभालते हुए, वे रणनीतिक रूप से तय करते हैं कि स्थगन की संभावना, मामले का महत्व या किसी विशेष न्यायाधीश की कथित मनोदशा और पूर्वाग्रह जैसे कारकों के आधार पर किस मामले पर ध्यान देना है।
  o इससे अक्सर कुछ मामलों में स्थगन होता है।
- मामले की सुनवाई में अप्रत्याशितता: इस समस्या को और बढ़ा देती है। वकीलों को अक्सर इस बात की स्पष्ट समझ नहीं होती है कि किसी विशेष मामले की सुनवाई कब होगी या स्थगन की संभावना कितनी है, जिससे उनके लिए अपने शेड्यूल की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।
  o इसके अलावा, वकील स्थगन का अनुरोध कर सकते हैं या जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि न्यायाधीश स्थगन देने की संभावना रखते हैं, खासकर यदि उनके मुवक्किल ने स्पष्ट रूप से इसके लिए कहा है।
  o पूर्वानुमान की यह कमी और इसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाने वाला रणनीतिक व्यवहार केवल अदालती कार्यक्रमों में भीड़ को बढ़ाता है।
- अदालती भीड़ पर प्रभाव: स्थगन और अंतरिम आदेशों को बढ़ाने की प्रवृत्ति वकीलों की सक्रिय रूप से किसी मामले को आगे बढ़ाने में रुचि को और कम कर देती है।
  o वादियों के लिए, किसी मामले पर स्थगन प्राप्त करना अक्सर एक जीत के रूप में देखा जा सकता है, खासकर सिविल मामलों में जहां स्थगन आदेश किसी भी तत्काल प्रतिकूल कार्रवाई को रोक सकता है।
  o परिणामस्वरूप, एक बार स्थगन प्राप्त होने के बाद, त्वरित समाधान के लिए जोर देने में बहुत कम प्रोत्साहन हो सकता है, जिससे मामलों का बैकलॉग बढ़ जाता है।

स्थगन और अंतरिम आदेशों का प्रभाव

- मुकदमा शुरू होने से पहले, न्यायाधीश प्रत्येक गवाह की गवाही के लिए विशिष्ट तिथियों के साथ एक कार्यक्रम निर्धारित करता है, और तदनुसार, समन जारी किए जाते हैं।
- हालांकि, अदालती कार्यक्रम, स्थगन और प्रक्रियात्मक देरी में बदलाव के कारण गवाही का समय अक्सर अप्रत्याशित हो जाता है।
- इससे गवाहों की दैनिक दिनचर्या बाधित होती है, उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने, यात्रा की व्यवस्था करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अक्सर बिना यह जाने कि उन्हें कब गवाही देनी है।
- पूर्वानुमानित कार्यक्रम की कमी गवाहों को निराश करती है, उन पर वित्तीय बोझ डालती है, उन्हें अदालत में पेश होने से हतोत्साहित करती है और मुकदमे में देरी में योगदान देती है।

आगे का रास्ता: समग्र सुधार की आवश्यकता

- समग्र दृष्टिकोण: अदालती समय-निर्धारण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो नियमों और समय-सीमाओं से परे हो, और जो सभी अभिनेताओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता हो।

- मूल्यांकन: न्यायाधीशों का मूल्यांकन न केवल उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, बल्कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिक जटिल मामलों को प्रबंधित करने और हल करने की उनकी क्षमता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
- यूनिट सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है: ताकि जटिल मामलों को प्राथमिकता दी जा सके, जिनमें पर्याप्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे केस प्रबंधन की व्यापक श्रेणी को बढ़ावा मिलता है।
- अनिश्चितता को कम करने और अनावश्यक स्थगन से बचने के लिए वकीलों को बेहतर शेड्यूलिंग जानकारी की आवश्यकता है।
  o न्यायालयों को पूर्वानुमानित शेड्यूलिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, देरी के लिए दंड लागू करना चाहिए और शेड्यूल का पालन करने वाले वकीलों को पुरस्कृत करना चाहिए।
- स्थगन आदेशों से बचना: वादियों को स्थगन आदेशों और अंतरिम राहतों को विलंब की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसे आदेशों को अस्थायी बनाया जाना चाहिए और नियमित समीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए।
  o गवाहों को अदालत में पेश होने में अधिक पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यात्रा व्यय से परे अग्रिम सूचना और पर्याप्त मुआवजा शामिल हो।

निष्कर्ष

- तकनीकी समाधान केस प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं, वास्तविक समय अपडेट प्रदान कर सकते हैं और समयसीमा की निगरानी कर सकते हैं।
- न्यायालय शेड्यूलिंग बाधाओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जिससे समग्र न्यायिक दक्षता में सुधार होगा।
- सिस्टम के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए सुधार के बिना, कोई भी प्रक्रियात्मक परिवर्तन केवल कागजी सुधार बनकर रह जाएगा।